रिफिल बुकिंग का अलग प्रावधान नहीं

शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक करायी जा सकेगी : जोशी

नई दिल्ली, 25 मार्च. सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकेंगे जबकि आम ग्राहकों के लिए यह सीमा 25 दिन की है. मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान में एलपीजी रिफिल बुकिंग की सिर्फ दो समय सीमा है

– शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक करायी जा सकेगी. इसके अलावा किसी भी लाभार्थी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है. सरकार ने लोगों से भ्रामक जानकारियों से बचने और घबराहट में आकर जल्दबाजी में बुकिंग न कराने की अपील की है. स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और चिंता का कोई कारण नहीं है. उल्लेखनीय है कि फरवरी तक ग्राहक सिलेंडर 21 दिन के अंतर पर अगला रिफिल बुक करा सकते थे लेकिन पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति में आयी बाधा को देखते हुए सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समयांतराल निर्धारित किया है.

पात्र व्यक्ति को मुफ्त राशन दिया जा रहा है

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत राशन पाने से वंचित नहीं किया जा रहा है. श्री जोशी ने प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड प्रमाणीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी न होने पर भी राशन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान से बिना राशन वापस नहीं किया जा रहा है. उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राशन दुकानों का आवंटन एवं राशन दुकानदारों का कमीशन राज्य सरकारें तय करती हैं.

एमउएम ने गुरुग्राम में अंताल्या हिल्स में कब्जा शुरू किया

नई दिल्ली, 25 मार्च. अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर एमउएम ने हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 79 स्थित अपनी प्रीमियम लो-राइज आवासीय परियोजना एमउएम अंताल्या हिल्स में कब्जे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपनी ने बताया कि इस परियोजना को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है. अरावली पर्वतमाला की तलहटी में 33 एकड़ में फैली इस परियोजना में 2,540 लो-राइज़ मकान हैं, जो 35.1 लाख वर्ग फुट में फैले हुए हैं. प्रत्येक टावर में केवल चार अपार्टमेंट हैं, जो बेहतर गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं. इस परियोजना में वर्तमान टिकट राशि लगभग 1.8 करोड़ रुपये और उससे अधिक है. परियोजना की अनुमानित विकास लागत लगभग 1,520 करोड़ रुपये है.

को-ऑपरेटिव डिविडेंड पर 3 साल की टैक्स छूट

वित्त मंत्री का ऐलान, को-ऑपरेटिव को मिलेगा लाभ

छोटे निवेशकों को राहत, डिविडेंड पर टैक्स नहीं

नई दिल्ली, 25 मार्च. केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट देने की घोषणा की है.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले का उद्देश्य छोटे निवेशकों और को-ऑपरेटिव सदस्यों को प्रोत्साहित करना है, ताकि अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़ सकें. सरकार का मानना है कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनकी मजबूती से रोजगार सृजन और ग्रामीण

विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस कदम से खासकर उन सदस्यों को फायदा होगा, जिनकी हिस्सेदारी कम है और जो डिविडेंड आय पर निर्भर रहते हैं.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले ले रही है, जिससे आर्थिक लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे. केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट देने का ऐलान किया है.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की, जिससे देशभर के छोटे को-ऑपरेटिव सदस्यों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने बताया कि यह टैक्स छूट विशेष रूप से नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से प्राप्त डिविडेंड आय पर लागू होगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य को-ऑपरेटिव संस्थाओं में कम हिस्सेदारी रखने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें. उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और किसान देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कोटक बैंक घोटाले की जांच एसीबी को सौंपने के आदेश

पंचकूला 25 मार्च.हरियाणा के सरकारी विभागों में 590 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है.

राज्य सरकार ने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को सौंपते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं.नगर निगम अधिकारियों को घोटाले की जानकारी मिलते ही बैंक और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया गया. इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सक्रियता दिखाते हुए पंचकूला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को शिकायत सौंपी. मामले की जांच डीसीपी कार्यालय द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इसे एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है. जानकारी के अनुसार, पंचकूला नगर निगम का सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में खाता था, जिसमें नगर निगम की 16 एफडी जमा थीं. ये एफडी एसबीआई बैंक से ट्रांसफर की गई थीं. जांच में सामने आया है कि इनमें से पांच एफडी का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मामले में बैंक की पूर्व कर्मचारी स्वाति और पुष्पिंद्र के नाम सामने आ रहे हैं.

गोल्ड-सिल्वर में जबरदस्त तेजी नए रिकॉर्ड कायम

1.44 लाख रुपए पर पहुंचा सोना

2.34 लाख रुपए पर आई चांदी

नई दिल्ली, 25 मार्च. देश में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों का ध्यान इस ओर गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम पर 5 हजार रुपये बढ़कर 1.45 लाख रुपये तक पहुंच गई है. वहीं, चांदी भी 9 हजार रुपये की छलांग लगाकर 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.इस साल की शुरुआत से ही सोना और चांदी लगातार तेजी

देश में सोना और चांदी की कीमतों में बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे दोनों की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 5,000 रुपये की बढ़त के साथ 1.45 लाख रुपये पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत 9,000 रुपये उछलकर 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

दिखा रहे हैं. बीते कुछ महीनों में सोने के दाम करीब 11 हजार रुपये और चांदी के दाम 3 हजार रुपये तक बढ़ चुके हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार-चढ़ाव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है.

नौ राज्यों को एफएमडी मुक्त घोषित कर डेयरी निर्यात बढ़ाने की योजना

नई दिल्ली, 25 मार्च. देश के नौ राज्य खुरपका-मुंहपका रोग से मुक्त हो चुके हैं और उन्हें इसका प्रमाणन दिलाकर देश का डेयरी निर्यात बढ़ाने की सरकार की योजना है. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है.

इसके बावजूद डेयरी उत्पादों के निर्यात में हम पीछे हैं क्योंकि कई देशों में डेयरी निर्यात के लिए एफएमडी मुक्त प्रमाणन जरूरी है. श्री सिंह ने कहा कि साल 2014-15 में हमारा दुग्ध उत्पादन 14.63 करोड़ टन से बढ़कर 24.8 करोड़ टन हो गया है.

टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में दो ट्रांसमिशन लाइनें कमीशन की

नई दिल्ली, 25 मार्च. टाटा पावर ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 154 सर्किट किलोमीटर में फैली दो ट्रांसमिशन लाइनों - 400 किलोवोल्ट टांडा-गोंडा और 400 किलोवोल्ट (केवी) गोंडा-बस्ती डबल सर्किट - की कमीशनिंग की घोषणा की.

कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इसके साथ ही उसने साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत सभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर लिया है. इस नेटवर्क में अब राज्य भर में 951 सर्किट किमी की तीन 765 केवी लाइनें, 566 सर्किट किमी की चौदह 400 केवी लाइनें और 3,460 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वाले तीन 765/400 केवी सबस्टेशन हैं.

टाटा पावर ने बताया कि चार ट्रांसमिशन लाइनों 765 केवी मैनपुरी-बारा सिंगल सर्किट लाइन, 765 केवी मैनपुरी-उन्नाव सिंगल सर्किट लाइन, 400 केवी टांडा-गोंडा और 400 केवी गोंडा-बस्ती डबल सर्किट लाइन की कमीशनिंग से उत्तर प्रदेश में उत्पन्न 4,000 मेगावाट से अधिक तापीय बिजली के सुरक्षित और विश्वसनीय निष्कासन में सहायता मिलेगी. इससे राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने, ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

खटवानी मोटर्स में नई रेनो डस्टर लॉन्च

नवभारत,जबलपुर। महाकौशल के अधिकृत विक्रेता खटवानी मोटर्स में बुधवार को नई रेनो डस्टर की लॉन्चिंग रामचंद्र खटवानी, रॉबिन खटवानी और ऋग्वेद खटवानी द्वारा की गई।
इस अवसर पर जनरल मैनेजर सचिन कौशिक ने बताया कि नई डस्टर का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट 10.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और देशभर में इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। नई डस्टर को एडवांस आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता प्रदान करता है। इसमें 163 पीएस पावर और 280 एनएम टॉर्क देने वाला टर्बो टीसीई 160 इंजन दिया गया है, जो मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, गूगल इंटीग्रेशन के साथ ओपन लिंक मल्टीमीडिया सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और 17 एडास फीचर्स शामिल हैं। लॉन्च के साथ ही इस वेरिएंट की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। वहीं 31 मार्च 2026 से पहले प्री-बुकिंग करने पर ग्राहकों को 10.29 रुपए लाख की विशेष शुरुआती कीमत का लाभ मिल रहा है।

अकासा ने साढ़े तीन साल में 2.5 करोड़ यात्रियों का बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 25 मार्च. नवोदित विमान सेवा कंपनी अकासा एयर ने संचालन शुरू करने के मात्र 42 महीनों (साढ़े तीन साल) से थोड़े अधिक समय में 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा देने की उपलब्धि हासिल कर ली है.

अकासा ने बुधवार को बताया कि वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे तेज भारतीय एयरलाइन बन गयी है. एयरलाइन ने अगस्त 2022 में पहली उड़ान भरी थी और लगातार उद्योग में उच्च पैसेंजर लोड फैक्टर दर्ज किया है. यह मांग की मजबूती, नेटवर्क की दक्षता और अकासा अनुभव के प्रति बढ़ती ग्राहक पसंद को दर्शाता है. इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए अकासा एयर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दूबे ने कहा, केवल साढ़े तीन साल में 2.5 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार करना हमारे लिए गर्व का विषय है.

भारत की जीडीपी 7.1% की दर से बढ़ेगी

नई दिल्ली, 25 मार्च. वैश्विक अनिश्चितताओं और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है. एसएंडपी ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

यह संकेत देता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए रखेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और निजी निवेश में सुधार भारत की आर्थिक मजबूती के प्रमुख आधार हैं. वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर सीमित रहने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि देश की विविध अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र की मजबूती भारत को बाहरी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है.

यही कारण है कि भारत एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है.

समाचार विशेष

मायावती का 3 राज्यों के लिए सीक्रेट प्लान

एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में 'शासक वर्ग' बनने का बड़ा दांव

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक सक्रियता काफी तेज कर दी है. लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की कमेटियों के साथ गहन मंथन किया.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में पार्टी के जनाधार को बढ़ाना और 'सत्ता की मास्टर चाबी' को अपने हाथों में लेना है. चुनावों के लिए मायावती की गुप्त योजना के तहत अब बसपा महज

उपस्थिति दर्ज कराने के बजाय सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए मैदान में उतरेगी.

मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा अब केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि 'शासक वर्ग' बनने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक में जीत का एक नया ब्लूप्रिंट साझा किया है जो पार्टी को आगामी चुनाव में नई दिशा देगा. बैठक में पिछली कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने और पार्टी को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. इन तीन राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए मायावती ने जमीनी स्तर पर काम करने और जनाधार बढ़ाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी सफलता अर्जित करना अब समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य मांग बन गई है.

सत्ता की मास्टर चाबी का लक्ष्य

लखनऊ के रणनीतिक मंथन में मायावती ने जोर देकर कहा कि जातिवादी शोषण और गरीब विरोधी शासन से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता सत्ता हासिल करना है. उन्होंने 'सत्ता की मास्टर चाबी' अपने हाथ में लेने की जरूरत बताते हुए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मिशनरी भावना के साथ जुटने को कहा. उनका मानना है कि जब तक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना कभी संभव नहीं है. बैठक के दौरान पुरानी रणनीतियों की समीक्षा की गई और आगामी महीनों के लिए नए संगठनात्मक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया ताकि चुनाव में बेहतर परिणाम मिलें.

केरल में केसीवी के चहेतों को टिकट

तिरुवनंतपुरम. केरल में कांग्रेस पार्टी में अलग घमासान चल रहा है. राहुल गांधी के सबसे नजदीकी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल यानी केसीवी ने टिकट बंटवारे में अपनी खूब चलाई है.

उन्होंने अपनी पसंद के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाई. कांग्रेस के एक जानकार नेता के मुताबिक केरल में कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की उसमें 17 लोग घोषित तौर पर केसीवी के करीबी हैं. पार्टी के दिग्गज नेता रमेश चेन्निथला के नौ करीबियों को टिकट मिली है, जबकि विधायक दल के नेता वीडी सतीशन की सिफारिश पर पांच लोगों को टिकट मिली है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 16 सांसदों में से शशि थरूर अकेले सांसद हैं, जो टिकट बंटवारे से दूर रहे. बाकियों को अपने क्षेत्र में एक या दो टिकट की सिफारिश करने का मौका मिला.

कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि उनमें भी केसीवी की पसंद चली. कुल माल कर 60 फीसदी के करीब सीटों पर केसीवी की पसंद के उम्मीदवार दिए जा रहे हैं.

ममता के शत्रु पहुचाएंगे भाजपा को फायदा!

कोलकाता. बंगाल चुनाव में एक नया गठबंधन सामने आया है. बंगाल के ओवैसी के साथ आ गए हैं हैदराबाद वाले ओवैसी. अब इस गठबंधन से ममता को नुकसान हो या ना हो लेकिन भाजपा को फायदा जरूर हो सकता है.

गौरतलब है कि ओवैसी को हमेशा से ही भाजपा की बी-टीम बोला जाता है. इस बीच जब हुमायूं कबीर भी बंगाल में उभरे तब उन्हें भी बीजेपी की बी-टीम कहा जाने लगा. अब हुमायूं कबीर तो यह साफ कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा और ममता बनर्जी दोनों से है लेकिन राजनीति में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है बल्कि होता वो है जो दिखाया नहीं जाता. खैर, हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेडीयूपी) ने पहले ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. इस गठबंधन में एआईएमआईएम भी साझेदार होगी और लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी हुमांयू कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की रूपरेखा रखेंगे. दरअसल, एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाए थे कि वह भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के करीबी हैं और उन्होंने कबीर को सुवेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा भी बताया था.

भाजपा को कैसे होगा फायदा?

ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तब वह किसी को हराने के उद्देश्य से नहीं लड़ती बल्कि वह तो मिशन की तरह चुनाव लड़ती है. बीजेपी अपने एजेंडा के साथ ही आगे बढ़ रही है. इसका सटीक उदाहरण ईद वाला दिन ही है, जहां ममता एकतरफ ईद मना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुवेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर में पूजा कर रहे थे. टीएमसी, ओवैसी और कबीर तीनों का टारगेटेड वोटबैंक अल्पसंख्यक हैं. ऐसे में वोट कटने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं.

विशेष अबकी बदल जाएगी कोलाथुर की हवा?

15 साल से स्टालिन का अभेद किला

चेन्नई. चेन्नई की घनी आबादी वाली गलियों के बीच स्थित 'कोलाथुर' कोई साधारण इलाका नहीं है. यह वह सीट है जिसने तमिलनाडु को उसका वर्तमान मुख्यमंत्री दिया है. एम.के. स्टालिन यहां से लगातार तीन बार जीत चुके हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहां की चुनौतियां किसी आम बस्ती से कम नहीं हैं.

ऊंची इमारतों और बढ़ते व्यापारिक केंद्रों के बीच यहां का आम नागरिक आज भी बारिश के

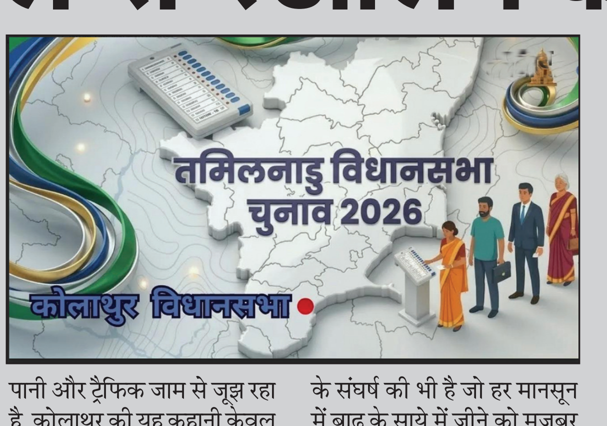

पानी और ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है. कोलाथुर की यह कहानी केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के संघर्ष की भी है जो हर मानसून में बाढ़ के साये में जीने को मजबूर हैं. कोलाथुर विधानसभा सीट आज पूरे तमिलनाडु की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है. डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने साल 2011, 2016 और फिर 2021 में यहां से जीत की हैट्रिक लगाई है. पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो स्टालिन ने 1,05,522 वोट हासिल कर 60.9 प्रतिशत के बड़े वोट शेयर के साथ एकतरफा जीत दर्ज की थी. उनके सामने एडीएमके के आदिराजाराम जैसे प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्हें मात्र 35,138 वोट मिले. यह आंकड़े साबित करते हैं कि यह सीट न केवल डीएमके का अभेद्य किला है, बल्कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत साख का प्रतीक भी है.

बढ़ती आबादी के बोझ तले दबता बुनियादी ढांचा- कभी अर्ध-औद्योगिक क्षेत्र रहा कोलाथुर आज एक विशाल शहरी आवासीय केंद्र में बदल चुका है. पेराम्बूर, विल्लीवक्कम और माधवराम के बीच स्थित यह इलाका अब बड़े अपार्टमेंट समूहों और व्यावसायिक कॉरिडोर से भरा हुआ है. यहां निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के साथ-साथ छोटे व्यापारी और प्रवासी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं.

क्या मिल जाएगा स्थायी समाधान?

कोलाथुर के मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द मानसून के दौरान आने वाली भीषण बाढ़ है. यहां के निवासियों की प्राथमिकता आज भी बाढ़ नियंत्रण और पानी की सुचारू सप्लाई है. खराब जल निकासी व्यवस्था, पुराने पड़ चुके ड्रेनेज सिस्टम पर अतिक्रमण और कचरा प्रबंधन की खामियां यहां के जीवन को कठिन बना देती हैं. व्यापारियों के लिए पार्किंग की कमी एक बड़ी समस्या है, तो वहीं बुजुर्ग पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते हैं.